RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 325
दि. 29.03.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल में सियासी टकराव का शिखर: आरोप-पत्र बनाम जवाब-पत्र की जंग तेज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर अपने चरम टकराव के दौर में पहुंच गई है, जहां चुनावी माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप की तीखी जंग खुलकर सामने आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को आक्रामक रूप दे दिया है। इसी क्रम में अमित शाह द्वारा जारी 14 बिंदुओं वाली 'चार्जशीट' ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है, जिसका जवाब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपने 'जवाब-पत्र' के जरिए दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि बंगाल का चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुका है। दोनों पक्ष एक-दूसरे को घेरने के लिए न केवल स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों को भी अपने राजनीतिक तर्कों में शामिल कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जो 'चार्जशीट' जारी की, उसमें उन्होंने टीएमसी के 15 वर्षों के शासन को "अराजकता और भ्रष्टाचार का युग" करार दिया। उनका कहना है कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने का अवसर नहीं, बल्कि राज्य की "आत्मा को बचाने" और उसे भयमुक्त बनाने का निर्णायक क्षण है। शाह ने अपने आरोपों में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक विफलताओं को प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखा।

सबसे प्रमुख मुद्दा जो अमित शाह ने उठाया, वह था घुसपैठ। उन्होंने दावा किया कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल इस समय घुसपैठ का मुख्य प्रवेश द्वार बन चुका है। उनके अनुसार, यदि राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव को नजरअंदाज किया है। अमित शाह ने अपने भाषण में व्यक्तिगत हमलों का भी सहारा लिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर "विक्टिम कार्ड" खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अक्सर सहानुभूति बटोरने के लिए नाटकीय परिस्थितियां पैदा करती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने

और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कथित असम्मान का भी मुद्दा उठाया।

भाजपा के इस आक्रामक रुख के जवाब में टीएमसी ने भी उतनी ही तीव्रता से पलटवार किया। पार्टी ने 'मोटा भाई-जवाब चाई' नाम से अपना आरोप-पत्र जारी करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी का यह दस्तावेज केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भाजपा-शासित राज्यों की विफलताओं को उजागर करने की कोशिश की गई है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे पर तीखा बयान देते हुए मणिपुर में जारी जातीय हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले तीन वर्षों से हिंसा की आग में जल रहा है, और इस पर केंद्र सरकार की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े करती है। उनके अनुसार, जब भाजपा अन्य राज्यों पर आरोप लगाती है, तो उसे पहले अपने शासन वाले राज्यों की स्थिति का भी जवाब देना चाहिए।

महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि वह बंगाल में "डिटेंशन कैंप मॉडल" लागू करना चाहती है, जैसा कि असम में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाली और बांग्लादेशी के बीच की रेखा को जानबूझकर धुंधला कर रही है, ताकि सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया जा सके और राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।

इस पूरे विवाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों में से 98 प्रतिशत विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं, जबकि दोषसिद्धि की दर बेहद कम है। यह आरोप केंद्र सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।

टीएमसी ने इस मुद्दे को बंगाली अस्मिता से भी जोड़ने की कोशिश की है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि बंगाल के लोग गौरवशाली इतिहास के धनी हैं और उन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अनुसार, भाजपा द्वारा बंगालियों को संदेह की नजर से देखना न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह सामाजिक विभाजन को भी बढ़ावा देता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनावी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा जहां कानून-व्यवस्था, घुसपैठ और भ्रष्टाचार के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में उतर रही है, वहीं टीएमसी सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय पहचान और केंद्र बनाम राज्य के मुद्दों को प्रमुखता दे रही है।

इस सियासी टकराव का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों दल अब भावनात्मक और प्रतीकात्मक मुद्दों को भी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा "राष्ट्रीय सुरक्षा" और "भयमुक्त समाज" की बात कर रही है, जबकि टीएमसी "गौरव, पहचान और अधिकार" के मुद्दों को उभार रही है।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मुकाबला बेहद तीखा और बहुआयामी होने वाला है। आरोप-पत्र और जवाब-पत्र की यह जंग केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी-अपनी छवि बनाने और विपक्ष को कमजोर करने की एक सुनियोजित रणनीति है।

अंततः यह फैसला जनता के हाथ में है कि वह किस नैरेटिव पर विश्वास करती है। क्या वह बदलाव के वादे को स्वीकार करती है, या फिर मौजूदा सरकार के कामकाज पर भरोसा बनाए रखती है। लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल का चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन चुका है।

तमिलनाडु चुनावी रण: डीएमके ने 164 सीटों पर ठोकी दावेदारी, गठबंधन समीकरण साफ

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अब सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख एम.के. स्टालिन ने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान करते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया है। कुल 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में डीएमके खुद 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी इस बार भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के इरादे से मैदान में उतरी है।

इस सीट बंटवारे में कांग्रेस को 28 सीटें दी गई हैं, जो गठबंधन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं। डीएमके ने अपने सहयोगियों के बीच सीटों का संतुलित वितरण कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि गठबंधन एकजुट है और चुनावी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है।

सबसे दिलचस्प पहलू डीएमडीके को लेकर सामने आया है। देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) को इस बार 10 सीटें दी गई हैं, जिसे राजनीतिक विश्लेषक एक रणनीतिक कदम मान रहे हैं। इसके अलावा विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) को 8 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को 5-5 सीटें दी गई हैं। वहीं मरुमलार्चि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 4 सीटें मिली हैं।

अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने की रणनीति के तहत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और मणिथनेया मक्कल काची (एमएमके) को 2-2 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा छोटे सहयोगियों में मक्कल जननायक काची और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को 1-1 सीट देकर गठबंधन का दायरा और व्यापक किया गया है।

इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है, वह है ओ. पनीरसेल्वम। कभी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे पनीरसेल्वम अब डीएमके गठबंधन की ओर से बोडिनायकन्नूर सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह राजनीतिक घटनाक्रम तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।

विश्लेषकों का मानना है कि स्टालिन ने पनीरसेल्वम को अपने साथ जोड़कर दक्षिण तमिलनाडु के महत्वपूर्ण 'मुकुलथोर' वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से एआईएडीएमके का गढ़ माना जाता रहा है, ऐसे में पनीरसेल्वम की उम्मीदवारी वहां चुनावी समीकरण बदल सकती है।

डीएमके का यह सीट बंटवारा केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी ने जहां अपने मजबूत क्षेत्रों में खुद उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, वहीं सहयोगियों को उनके प्रभाव वाले इलाकों में मौका देकर गठबंधन की ताकत को अधिकतम करने की कोशिश की है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इस बार तमिलनाडु का चुनाव केवल डीएमके और एआईएडीएमके के बीच पारंपरिक मुकाबला नहीं रहेगा, बल्कि इसमें गठबंधन की मजबूती, क्षेत्रीय समीकरण और व्यक्तिगत नेताओं का प्रभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्टालिन के इस कदम से यह साफ हो गया है कि डीएमके इस चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और हर मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। सीटों का यह बंटवारा न केवल पार्टी की चुनावी तैयारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि डीएमके आगामी चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष, खासकर एआईएडीएमके, इस रणनीति का किस तरह जवाब देता है और चुनावी मैदान में क्या नए समीकरण उभरकर सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल, डीएमके ने अपनी चाल चल दी है और तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी शतरंज की बिसात पूरी तरह सज चुकी है।

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: लूथरा भाइयों को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

पणजी। गोवा के चर्चित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब अग्निकांड मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। मापुसा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

यह मामला 6 दिसंबर 2025 को अर्पोरा में हुए उस भीषण अग्निकांड से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 'बर्च बाय रोमियो लेन' नामक नाइटक्लब में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना ने न केवल गोवा की पर्यटन छवि पर सवाल खड़े किए, बल्कि सुरक्षा मानकों को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर दीं।

घटना के तुरंत बाद दोनों आरोपी देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे, जिससे उनकी मंशा पर और भी संदेह गहराया। हालांकि, पुलिस की तत्परता के चलते 17 दिसंबर को उन्हें भारत वापस लाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों आरोपी कोलवाले सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने को इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह राहत देने से इनकार किया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है that इस तरह के मामलों में, जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान गई हो और आरोप गंभीर हों, अदालतें आमतौर पर सख्त रुख अपनाती हैं।

इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां दो अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रही हैं। एक ओर अंजुना पुलिस आग लगने के कारणों, अग्नि सुरक्षा उपायों की स्थिति और संभावित लापरवाही की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि नाइटक्लब में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिससे आग तेजी से फैल गई और लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका।

दूसरी ओर मापुसा पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्लब को संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस कैसे मिला। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक्साइज लाइसेंस प्राप्त किया था। आरोप है कि स्वास्थ्य अधिकारी के नकली हस्ताक्षर और फर्जी एनओसी (NOC) का इस्तेमाल कर नियमों को दरकिनार किया गया।

यदि ये आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला केवल लापरवाही का नहीं, बल्कि सुनियोजित फर्जीवाड़े का भी बन जाएगा। इससे यह भी सवाल उठता है कि संबंधित विभागों में निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है।

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश की प्रति मिलने के बाद ही आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी। संभव है कि वे उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील करें।

इस अग्निकांड ने एक बार फिर देशभर में सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर नाइटक्लब, मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा मानकों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से पालन और नियमित निरीक्षण भी जरूरी है।

गोवा, जो अपनी नाइटलाइफ और पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहां इस तरह की घटना ने प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी का काम किया है। राज्य सरकार ने इस घटना के बाद सुरक्षा मानकों की समीक्षा और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।

पीड़ितों के परिवारों के लिए यह हादसा एक ऐसा घाव है, जो शायद ही कभी भर सके। वे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अदालत का यह फैसला उनके लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है।

कुल मिलाकर, यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, नियमों की अनदेखी और लालच के खतरनाक परिणामों का उदाहरण बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच और अदालत की कार्यवाही इस बात को तय करेगी कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को कितना और किस प्रकार का दंड मिलता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक

- पेट्रोल, डीजल और गैस आदि के स्टॉक और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई
- राज्य में गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद सहित आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है
- मुख्यमंत्री ने मौजूदा समय में सभी विभागों को सतर्क रहकर, तालमेल और टीम वर्क के साथ काम करने के निर्देश दिए

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में शनिवार को गांधीनगर में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस सहित दूसरी आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक, वितरण व्यवस्था और इन वस्तुओं को लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अभी पूरे राज्य में गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद सहित आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की हैं कि भविष्य में भी इन वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने भी इस

बैठक में उपस्थित रहकर कई सुझाव दिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मौजूदा वैश्विक हालातों के परिप्रेक्ष्य में देश के राज्यों में पेट्रोल, डीजल, गैस, उर्वरक और खाद्य आपूर्ति की स्थिति को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में आज राज्य के वरिष्ठ सचिवों की बैठक हुई।

मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कहा कि मौजूदा समय में सभी विभागों को सतर्क रहकर, तालमेल और टीम वर्क के साथ काम करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहे।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि राज्य में पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को राज्य में तेजी से लागू करके नए पीएनजी कनेक्शन तेजी से दिए जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि, विशेषकर रिहायशी क्षेत्रों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्पिटलों को ऐसे कनेक्शन देने में वरीयता दी जाए।

गुजरात देश में सर्वाधिक 23 फीसदी पीएनजी कनेक्शन वाला राज्य है। इसके अलावा, देश के 12 फीसदी सीएनजी फिलिंग स्टेशन भी राज्य में कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री की राज्यों को ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शंस देने के लिए की गई हिमायत के बाद राज्य में नए कनेक्शन देने नका काम युद्धस्तर पर शुरू किया गया है। पिछले 10 दिनों में 12 हजार से अधिक नए पीएनजी कनेक्शंस और 300 से अधिक नए कमर्शियल कनेक्शंस दिए गए हैं।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रेजेंटेशन में बताया गया कि राज्य में 1.28 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। इतना ही नहीं, इन घरेलू कनेक्शन धारकों को नियमित गैस आपूर्ति में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए राज्य सरकार ऑयल एंड गैस कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है।

राज्य सरकार द्वारा एलपीजी कनेक्शन धारकों की किसी भी समस्या के त्वरित निवारण के लिए कार्यरत की गई हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 10,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर निगरानी रखने और उनके खिलाफ कठोरता से पेश आकर अनुकरणीय सजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के मन में इन वस्तुओं की कमी या किल्लत के गलत भय को दूर किया जा सकेगा।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में फर्टिलाइजर का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कृषि विभाग ने इस प्रकार का आयोजन किया है कि किसानों को खरीफ सीजन के लिए खाद की कोई समस्या नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में यह सुनिश्चित करने का भी मार्गदर्शन दिया कि राज्य के बंदरगाहों पर कार्गो का सुचारू संचालन और निगरानी हो, साथ ही कंजेशन (जाम) होने के कारण सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राज्य में श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए, जिससे कि उन्हें मौजूदा वैश्विक हालातों के कारण आर्थिक मुश्किलों का सामना न करना पड़े।

बैठक में केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाने और जिलों में सप्लाई चेन को सुचारू रखने के मार्गदर्शन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। जिला स्तर पर ऐसी समन्वय समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यरत होगी।

इस वैश्विक संकट के समय में अनिवासी गुजरातियों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्प लाइन शुरू की गई है और एनआरआई प्रभाग को अनिवासी गुजरातियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

चुनावी पारदर्शिता की नई बहस: पोलिंग बूथ पर बायोमीट्रिक प्रणाली लागू करने की मांग

नई दिल्ली। देश की चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाने को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका ने इस चर्चा को केंद्र में ला दिया है। इस याचिका में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को आगामी विधानसभा चुनावों में बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता, जो पेशे से एक वकील हैं, का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में मौजूद खामियों को दूर करने और "एक नागरिक, एक वोट" के संवैधानिक सिद्धांत को सख्ती से लागू करने के लिए अब तकनीक का सहारा लेना अनिवार्य हो गया है। उनके अनुसार, यदि मतदान के दौरान फिंगरप्रिंट और आइरिस (पुतली) स्कैन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए, तो फर्जी मतदान, दोहरी वोटिंग और तथाकथित "घोस्ट वोटिंग" जैसी समस्याओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर चुनाव में करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इतनी विशाल प्रक्रिया को निष्पक्ष और त्रुटिरहित बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) जैसी प्रणालियों को लागू कर पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद समय-समय पर चुनावी धांधली के आरोप सामने आते रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि बायोमीट्रिक डेटा हर व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है और इसकी नकल करना लगभग असंभव है। ऐसे में यदि मतदान केंद्रों पर मतदाता की पहचान बायोमीट्रिक माध्यम से सत्यापित की जाए, तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी के नाम पर वोट डालने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा दोनों मजबूत होंगे।

हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का। भारत में पहले ही आधार (Aadhaar) से जुड़े डेटा के उपयोग और उसकी सुरक्षा को लेकर बहस होती रही है। ऐसे में यदि चुनावी प्रक्रिया में बायोमीट्रिक डेटा का उपयोग किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि मतदाताओं की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसका दुरुपयोग न हो।

इसके अलावा, तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई जगहों पर इंटरनेट और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हर पोलिंग बूथ पर बायोमीट्रिक उपकरणों को स्थापित करना और उन्हें सुचारू रूप से संचालित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों, प्रशिक्षण और समय की आवश्यकता होगी।

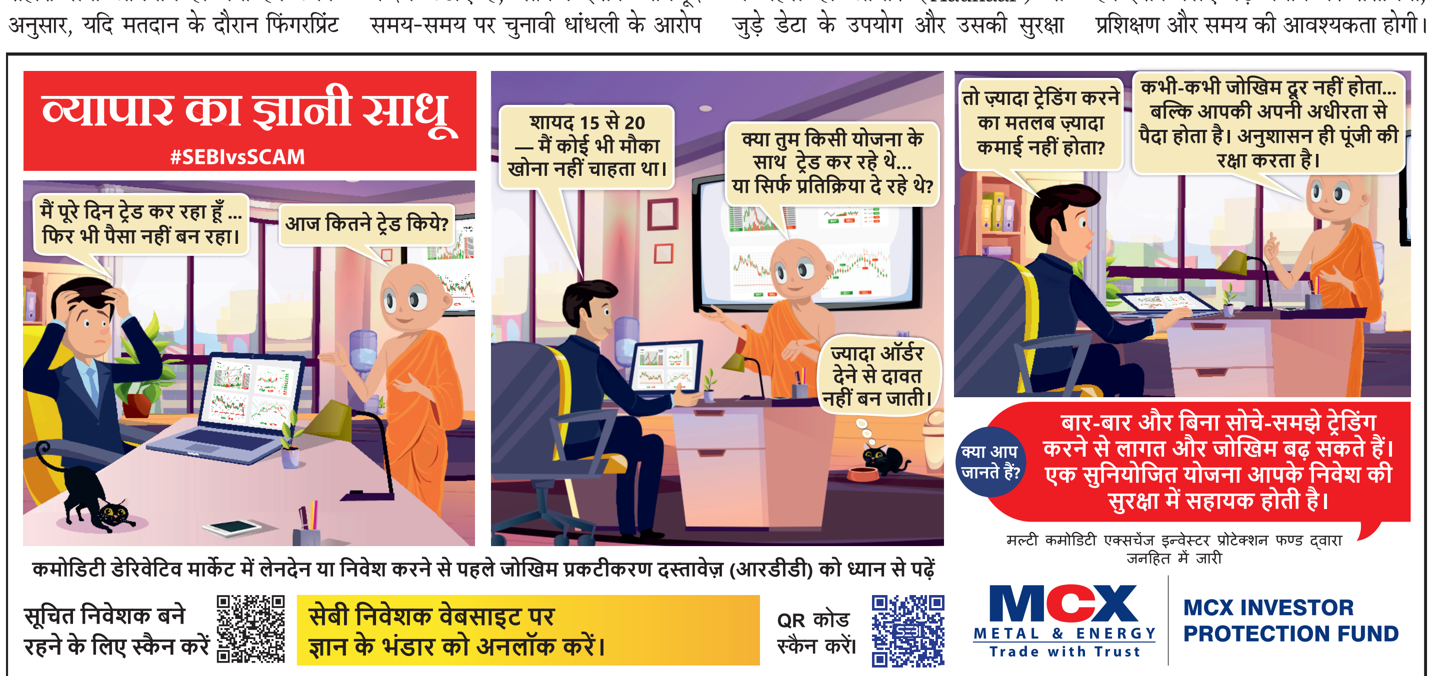

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फण्ड द्वारा जनहित में जारी
कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में लेनदेन या निवेश करने से पहले जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़ (आरडीडी) को ध्यान से पढ़ें
सूचित निवेशक बने रहने के लिए स्कैन करें
सेबी निवेशक वेबसाइट पर ज्ञान के भंडार को अनलॉक करें।
QR कोड स्कैन करें।
MCX METAL & ENERGY Trade with Trust
MCX INVESTOR PROTECTION FUND

संपादकीय

सोशल मीडिया पर अंकुश

अमेरिका में लॉस एंजेलिस की एक जूरी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के घातक प्रभावों से त्रस्त एक युवती के पक्ष में सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से दुनिया भर के अभिवावकों को राहत मिली है। दरअसल, सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़े एक मामले में मेटा और यूट्यूब पर 56 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि एक युवती ने मेटा और यूट्यूब पर आरोप लगाया था कि इनकी वजह से उसे सोशल मीडिया की घातक लत लगी। हालांकि, अब तक ये कंपनियां दलील देती रही हैं कि वे मात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और इसकी सामग्री के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट में वकीलों ने पीड़िता के पक्ष में दलील दी कि जानबूझकर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि उपयोगकर्ता कथित सोशल मीडिया की लत के शिकार बन जाएं। शुरुआत से पहचान गुप्त रखने वाली बीस वर्षीय युवती केली के वकीलों की दलील को जूरी ने स्वीकार किया कि इस लत से उसकी मानसिक सेहत को नुकसान हुआ है। जूरी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों की दलीलों को दरकिनार करते हुए मेटा और यूट्यूब पर साठ लाख अमेरिकी डॉलर यानी छप्पन करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। जूरी ने माना कि गूगल तथा मेटा ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संचालन में अपने मुनाफे के मद्देनजर अनुचित उपायों का सहारा लिया है। जूरी ने इसे अनैतिक भी बताया। जूरी के निर्णय के अनुसार इस मामले में जुर्माने की सत्तर फीसदी राशि मेटा तथा तीस फीसदी रकम गूगल को चुकानी होगी। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विरुद्ध हजारों मुकदमें चल रहे हैं। जिसमें कई वे लोग भी शामिल हैं जिनके बच्चों ने सोशल मीडिया की लत का शिकार होकर आत्मघाती कदम उठाये हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों में अभिभावक इस लत से बच्चों को बचाने के लिये आंदोलन करते रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका में ही विभिन्न अदालतों में सोशल मीडिया के घातक प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिये सैकड़ों मामले चल रहे हैं।

विश्वास किया जा रहा है कि इस मुकदमे के फैसले का प्रभाव उन तमाम मामलों में भी पड़ सकता है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहे हैं। हालांकि, दोषी पाये गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्ताधर्ता इस फैसले से असहमति जताते हुए इसके खिलाफ अपील करने की बात कर रहे हैं। उनकी दलील है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव के अनेक अन्य कारण हो सकते हैं, जिसके लिये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यूट्यूब के अधिकारियों का कहना है कि ये सोशल मीडिया साइट नहीं, सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जबकि पीड़ित युवती के वकीलों की दलील थी कि मेटा आदि कंपनियों ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की संरचना ऐसी बनायी है कि किशोरों को इसकी आदत लग जाए। हकीकत ये है कि भारत समेत दुनिया के करोड़ों किशोर इसकी लत के शिकार बन रहे हैं। यही वजह है हफ्तों चले मुकदमे के दौरान बड़ी संख्या में किशोरों के अभिभावक वादी के पक्ष में अदालत के परिसर में मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इस फैसले से पहले न्यू मेक्सिको में एक जूरी ने मेटा को इस बात के लिये जवाबदेह ठहराया कि उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वयस्कों की सामग्री तक बच्चों की पहुंच बनी है, जिससे उनके जीवन में यौन अपराधियों का खतरा बढ़ गया है।, भारत समेत कई विकसित व विकासशील देशों में सोशल मीडिया से बच्चों के जीवन में पड़ने वाले घातक प्रभावों को लेकर चिंता सालों से बनी हुई है। लेकिन देश में इस बाबत कोई नियामक कानून न होने से कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आती। बच्चों की पढ़ाई खराब होने और उनके मानसिक रोगों से ग्रस्त होने की आशंका से अब अभिभावक आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं। यही वजह है कि दुनिया के विकसित देशों में इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म से बच्चों को दूर रखने के लिए कानून बन रहे हैं। आस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस और अब अन्य यूरोपीय देश भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं ताकि एक निर्धारित आयु से ऊपर के बच्चे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना सकें।

Iran के लिए दिन-रात आंसू बहाने वाले कश्मीरी नेताओं ने कभी पंडितों के साथ क्यों नहीं दिखाई हमदर्दी?

> अगर मीरवाइज सच में अमन के दूत हैं, तो अपने दिल्ली दौरे के दौरान वह कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में जाकर उनसे क्यों नहीं मिले? अगर मीरवाइज सच में अमन के दूत हैं तो क्या कश्मीरी पंडितों से मिलकर उनसे वापस अपने घर लौटने का आग्रह नहीं करना चाहिए था?

मीरवाइज उमर फारूक ने नयी दिल्ली में ईरान के राजदूत से मुलाकात कर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया और ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त की। लेकिन सवाल यह है कि जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से मार कर भगाया जा रहा था तब यह संवेदना कहां थी? तब अमन का पैगाम लेकर ये नेता सामने क्यों नहीं आए थे? क्या उस दौर में इंसानियत की जरूरत नहीं थी? क्या तब किसी प्रतिनिधिमंडल को कश्मीरी पंडितों के घरों तक जाने की फुर्सत नहीं मिली थी? सवाल उठता है कि क्यों आज अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर इतनी सक्रियता दिखती है, लेकिन अपने ही समाज के जख्मों पर सन्नाटा छा जाता है? क्या यह चयनात्मक संवेदनशीलता नहीं है? क्या एक धर्म विशेष के लिए ही एकजुटता दिखाना अब राजनीति का हिस्सा बन गया है? अगर मीरवाइज सच में अमन के दूत हैं, तो अपने दिल्ली दौरे के दौरान वह कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में जाकर उनसे क्यों नहीं मिले? अगर मीरवाइज सच में अमन के दूत हैं तो क्या कश्मीरी पंडितों से मिलकर उनसे वापस अपने घर लौटने का आग्रह नहीं करना चाहिए था? देखा जाये तो कश्मीर में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन होते हैं, दान अभियान चलते हैं, बड़े नेता दूतावास पहुंचते हैं, लेकिन क्या कभी कश्मीरी पंडितों के लिए ऐसा कोई व्यापक अभियान चला? क्या उनके दर्द को उसी गंभीरता से लिया गया? सवाल उठता है कि आखिर यह दोहरा मापदंड क्यों है? क्यों एक समुदाय के मुद्दे पर भावनाएं उमड़ती हैं और दूसरे पर खामोशी छा जाती है? क्या संवेदनाएं भी चयनात्मक हो गई हैं? जहां तक मीरवाइज के दिल्ली दौरे की बात है तो आपको बता दें कि श्रीनगर से कश्मीर के कई धार्मिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल नयी दिल्ली पहुंचा और ईरान के राजदूत से मुलाकात कर वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मीरवाइज उमर फारूक कर रहे थे। उन्होंने न केवल संवेदना व्यक्त की, बल्कि ईरान के लोगों के साथ एकजुटता भी दिखाई। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाते हुए युद्ध की निंदा की और शांति बहाल होने की उम्मीद जताई।

असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह वही कश्मीर नहीं है जहां कभी हजारों कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़ कर भागना पड़ा था। क्या यह वही घाटी नहीं है जहां उनके कत्लेआम की खबरें आई थीं। तब यह धार्मिक संगठन, यह मौलाना, यह नेता कहां थे। तब अमन का संदेश क्यों नहीं दिया गया। तब किसी प्रतिनिधिमंडल ने पंडितों के आंसू पोंछने की कोशिश क्यों नहीं की?

मीरवाइज उमर फारूक और उनके साथियों ने ईरान के साथ गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों की बात कही। उन्होंने कश्मीर को ईरान ए सगीर तक बताया। यह बयान बताता है कि उनकी सोच किस दिशा में झुकी हुई है। लेकिन क्या उन्हें यह याद नहीं कि कश्मीर की पहचान केवल किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि उसकी विविधता से रही है। कश्मीरी पंडित उस पहचान का अभिन्न हिस्सा थे और हैं।

दिल्ली में ईरानी राजदूत से मिलना, संवेदना जताना, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देना आसान है। लेकिन क्या कभी इन नेताओं ने दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में जाकर उनसे मुलाकात की। क्या उन्होंने कभी उन्हें वापस घाटी आने का भरोसा दिलाया। अगर मीरवाइज सच में अमन का पैगाम देना चाहते, तो उन्हें सबसे पहले अपने घर के जख्म भरने चाहिए थे।

यह भी गौर करने वाली बात है कि कश्मीर में खामेनेई की मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, दान अभियान चलाए गए, लोगों ने पैसा, सोना, यहां तक कि मवेशी तक दान दिए। राजनीतिक नेताओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नाम ईरानी दूतावास पहुंचे और अपनी संवेदना दर्ज कराई। यह सक्रियता बताती है कि एक खास मुद्दे पर कितनी तेजी से लामबंदी हो सकती है।

लेकिन यही सक्रियता कश्मीरी पंडितों के मामले में क्यों नहीं दिखी? क्यों उनके दर्द को नजरअंदाज किया गया? क्यों उनके लिए कोई बड़े स्तर का अभियान नहीं चला, यही वह सवाल है जो आज कश्मीर के नेतृत्व की नीयत और प्राथमिकताओं पर गहरे संदेह खड़े करता है।

सच यह है कि अमन का पैगाम चयनात्मक नहीं हो सकता। अगर आप सच में शांति चाहते हैं, तो आपको हर पीड़ित के साथ खड़ा होना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। केवल एक धर्म विशेष के साथ एकजुटता दिखाना और दूसरे की पीड़ा को अनदेखा करना न तो नैतिक है और न ही स्वीकार्य।

आज जरूरत है कि कश्मीर के नेता आत्ममंथन करें। उन्हें यह समझना होगा कि असली परीक्षा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयान देने में नहीं, बल्कि अपने ही समाज के घावों को भरने में है। जब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान की गारंटी नहीं होगी, तब तक अमन का हर दावा खोखला ही रहेगा।

प्रेरणा

सम्मान का सच्चा अर्थ: जब एक राष्ट्रपति ने सिखाया मानवता का पाठ

भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का जीवन केवल उपलब्धियों और वैज्ञानिक सफलताओं की कहानी नहीं है, बल्कि वह मानवीय मूल्यों, विनम्रता और सम्मान के अद्भुत उदाहरणों से भरा हुआ है। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी सरलता और आत्मीयता थी, जो हर किसी को सहज ही प्रभावित कर देती थी। यह घटना भी उसी महान सोच और व्यवहार का प्रतीक है, जिसने उन्हें न केवल एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनाया, बल्कि एक सच्चा इंसान भी।

जब वे भारत के राष्ट्रपति थे, तब उन्हें एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम भव्य था, मंच सजा हुआ था, और उपस्थित लोग उत्साह से भरे हुए थे। सभी की नजरें केवल एक ही व्यक्ति पर थीं—डॉ. कलाम। उन्होंने अपने प्रेरणादायक शब्दों से सभी को उत्साहित किया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन असली सीख उस समय मिली, जब कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और अधिकांश लोग वहां से जा चुके थे।

डॉ. कलाम जब मंच से नीचे उतरे, तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा, जिसे शायद बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते। एक साधारण कर्मचारी चुपचाप कुर्सियां समेट रहा था। वह बिना किसी शोर-शराबे के अपना काम कर रहा था, जैसे यह उसका रोज का काम हो और उसमें कोई विशेष बात न हो। लेकिन डॉ. कलाम की नजरों में हर कार्य और हर व्यक्ति का महत्व था।

वे सीधे उस कर्मचारी के पास गए। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी, जो हमेशा लोगों को अपनेपन का एहसास कराती थी। उन्होंने उस कर्मचारी से कहा, "आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था संभाली।" यह सुनकर वह कर्मचारी स्तब्ध रह गया। शायद उसने अपने जीवन में पहली बार किसी इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह का सम्मान पाया था। उसकी आंखों में जो भाव थे, वे शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते—आश्चर्य, खुशी और आत्मसम्मान का अद्भुत मिश्रण।

उस एक क्षण ने उस कर्मचारी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। उसे महसूस हुआ कि उसका काम भी महत्वपूर्ण है, कि वह भी समाज के लिए कुछ योगदान दे रहा है, और उसका भी सम्मान है। यह भावना किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है।

इस घटना का प्रभाव केवल उस कर्मचारी तक ही सीमित नहीं रहा। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी यह दृश्य देखा और वे गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें यह समझ में आया कि सच्ची महानता केवल बड़े पद या उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।

डॉ. कलाम ने इसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी भूमिका में हो, सम्मान का अधिकारी है। यह केवल एक कथन नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सिद्धांत था, जिसे वे हर दिन अपने आचरण से जीते थे।

समाज में अक्सर काम के आधार पर लोगों को आंका जाता है। कुछ कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि कुछ को कमतर समझा जाता है। लेकिन यह दृष्टिकोण गलत है। हर काम, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, समाज के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई एक छोटा सा काम भी न हो, तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। डॉ. कलाम की इस सोच में एक गहरी मानवीय संवेदना छिपी हुई थी। वे जानते थे कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष करता है, मेहनत करता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। इसलिए हर किसी को सम्मान देना केवल एक नैतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता भी है।

इस घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। एक छोटी सी सराहना, एक धन्यवाद या एक मुस्कान किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह किसी के आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, उसे प्रेरित कर सकती है और उसे अपने काम के प्रति और अधिक समर्पित बना सकती है।

उस कर्मचारी ने भी इस घटना के बाद अपने काम को और अधिक लगन और समर्पण के साथ करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब वह केवल एक काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपने काम में गर्व महसूस हो रहा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसका योगदान भी महत्वपूर्ण है और उसकी मेहनत की कद्र होती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा हमें करना चाहिए? क्या हम उन लोगों को धन्यवाद कहते हैं, जो हमारे जीवन को आसान बनाने में योगदान देते हैं? क्या हम हर व्यक्ति को उसके कार्य के लिए सम्मान देते हैं?

अक्सर हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम इन छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम सच में एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना सीखना होगा, चाहे वह किसी भी पद या स्थिति में क्यों न हो।

डॉ. कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। उन्होंने कभी अपने पद या शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि हमेशा लोगों के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। यही कारण है कि वे आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।

उनकी यह छोटी सी घटना हमें एक बड़ा संदेश देती है—सम्मान देना सीखिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में खास है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो हम न केवल उनका, बल्कि अपने समाज का भी उत्थान करते हैं।

अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि एक समाज की सच्ची पहचान उसके लोगों के व्यवहार से होती है। यदि हम एक-दूसरे के प्रति सम्मान और संवेदना रखें, तो हमारा समाज न केवल मजबूत होगा, बल्कि अधिक मानवीय भी बनेगा। और यही वह संदेश है, जिसे ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने अपने जीवन और अपने कार्यों के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाया।

वैश्विक संकट के बीच मानवता की अंतिम सुरक्षा-रेखा है ऊर्जा संरक्षण

आज जब विश्व एक बार फिर भू-राजनीतिक तनावों के दौर से गुजर रहा है और ईरान, अमेरिका तथा इजरायल के बीच टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है, तब ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन चुकी है। तेल और गैस के दामों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या आधुनिक सभ्यता ने अपनी बुनियाद अत्यधिक अस्थिर संसाधनों पर खड़ी कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि मानवता की सुरक्षा का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय बनकर उभर रहा है। ऊर्जा आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वह उद्योगों की मशीनें हों, परिवहन के साधन हों, डिजिटल अर्थव्यवस्था हो या घरेलू जीवन की सुविधाएं किंतु विडंबना यह है कि जिस ऊर्जा पर हमारी प्रगति आधारित है, वही अब संकट का कारण बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की 'एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024' के अनुसार आने वाले दशक में वैश्विक ऊर्जा मांग में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जबकि जीवाश्म ईंधनों के भंडार तेजी से सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में यदि ऊर्जा संरक्षण और दक्षता को प्राथमिकता नहीं दी गई तो भविष्य में ऊर्जा संकट केवल आर्थिक चुनौती नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक अस्थिरता और वैश्विक संघर्षों का कारण भी बन सकता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य इस खतरे को और स्पष्ट करता है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो रही हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। दरअसल भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में वैश्विक संकट का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। पैट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि केवल परिवहन लागत को नहीं बढ़ाती बल्कि खाद्य पदार्थों से लेकर निर्माण सामग्री तक हर क्षेत्र में महंगाई को जन्म देती है। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है।

भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और यहां ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 'इंडिया एनर्जी आउटलुक 2024' रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में यदि ऊर्जा खपत को संतुलित नहीं किया गया तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को अपनी नीति का केंद्रीय तत्व बनाया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और 'उजाला' जैसे कार्यक्रमों ने यह साबित किया है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण और उससे हुई 48 बिलियन यूनिट बिजली की बचत इस बात का प्रमाण है कि यदि नीति और जनभागीदारी साथ आएं तो ऊर्जा संरक्षण एक जनांदोलन बन सकता है।

ऊर्जा संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी नई तकनीक या बड़े निवेश पर निर्भर नहीं है बल्कि यह हमारे दैनिक व्यवहार में छोटे-छोटे बदलावों से ही संभव है। उदाहरण के लिए, अनावश्यक रूप से जलती लाइटों को बंद करना, ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना, एयर कंडीशनर का सीमित प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन को अपनाना और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना, ये सभी कदम न केवल ऊर्जा बचाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। यदि भारत का प्रत्येक परिवार प्रतिदिन केवल एक यूनिट बिजली की बचत करे तो यह देश के लिए ऊर्जा क्रांति के समान होगा। ऊर्जा संरक्षण का संबंध केवल बिजली तक सीमित नहीं है बल्कि यह जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन में जल का व्यापक उपयोग होता है और जल की बर्बादी सीधे ऊर्जा की बर्बादी में बदल जाती है। इसी प्रकार, ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। आज जब दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तब ऊर्जा संरक्षण इस दिशा में सबसे प्रभावी हथियार साबित हो सकता है।

अक्षय ऊर्जा इस संकट का दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करती है लेकिन इसकी सफलता भी ऊर्जा संरक्षण पर ही निर्भर करती है। सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्रोतों का विस्तार तभी प्रभावी होगा, जब ऊर्जा की कुल मांग को नियंत्रित किया जाए। भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और स्मार्ट ग्रिड जैसी तकनीकें इस दिशा में नई संभावनाएं खोल रही हैं लेकिन इन सबका मूल आधार ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही है। शहरीकरण के बढ़ते दबाव ने भी ऊर्जा खपत को तेजी से बढ़ाया है। महानगरों में ऊंची इमारतें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बढ़ती वाहन संख्या ऊर्जा की मांग को कई गुना बढ़ा देती है। ऐसे में हरित भवन निर्माण, सौर पैनलों का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है।

अभियान

मांगलिक दोष से राहत का प्राचीन रहस्य: उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर की भात पूजा क्यों है इतनी प्रभावशाली

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का प्रभाव केवल आकाश तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे मानव जीवन के हर पहलू से गहराई से जोड़ा गया है। इन्हीं ग्रहों में मंगल ग्रह का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे साहस, ऊर्जा, रक्त, भूमि, युद्धक क्षमता और विवाह का कारक माना जाता है। जब मंगल अनुकूल होता है, तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता का विकास होता है, लेकिन जब यही ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होता है, तब यह जीवन में कई प्रकार की बाधाओं और कष्टों का कारण बनता है। इस स्थिति को ही आम भाषा में "मंगल दोष" या "मांगलिक दोष" कहा जाता है। मांगलिक दोष विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। जिन लोगों की कुंडली में यह दोष होता है, उनके विवाह में देरी, रिश्तों में अस्थिरता, दांपत्य जीवन में तनाव, क्रोध की अधिकता, आर्थिक संकट और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में इस दोष के निवारण के लिए अनेक उपाय, पूजा और तीर्थ स्थलों का विशेष महत्व बताया गया है।

इनमें सबसे प्रमुख और प्रभावशाली स्थान माना जाता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह मंदिर मंगल देव का जन्मस्थान है। यह पवित्र मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो स्वयं में एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरपूर स्थान माना जाता है।

पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, मंगल देव की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से हुई थी। यही कारण है कि मंगल का स्वभाव उग्र, तेज और अग्नि तत्व से युक्त माना जाता है। जब यह उग्रता असंतुलित हो जाती है, तो व्यक्ति के जीवन में अशांति और संघर्ष बढ़ने लगते हैं। ऐसे में इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विशेष पूजा और उपायों की आवश्यकता होती है।

मंगलनाथ मंदिर में होने वाली "भात पूजा" इसी उद्देश्य से की जाती है और इसे मंगल दोष निवारण का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। इस पूजा में चावल का विशेष महत्व होता है। चावल की प्रकृति ठंडी होती है, जो मंगल की उग्रता को शांत करने में सहायक मानी जाती है। जब भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पूजा को करते हैं, तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।

भात पूजा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा संतुलन की एक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर सकारात्मकता को ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन लाने में सहायक होती है।

उज्जैन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिष और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी अत्यंत विशेष रहा है। प्राचीन काल में यह नगर समय की गणना और ग्रहों की गति के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। इसलिए यहां स्थित मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह स्थान न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के अमलनेर में स्थित मंगल देव मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां मंगल देव की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है और विशेष रूप से मंगलवार के दिन यहां पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन अभिषेक और शांति पाठ के माध्यम से भक्त अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं।

मंगल दोष के निवारण के लिए केवल मंदिरों में पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कुछ सरल उपायों को नियमित रूप से अपनाना भी आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भगवान हनुमान की उपासना। हनुमान जी को मंगल का इष्ट देव माना जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं।

दान भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, गुड़ या लाल चंदन का दान करना शुभ माना जाता है। यह दान न केवल मंगल को प्रसन्न करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है।

मंत्र जाप भी एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। "ॐ भौमाय नमः" और "ॐ अंगारकाय नमः" मंत्रों का नियमित रूप से 108 बार जाप करने से मानसिक संतुलन बना रहता है और जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह मंत्र व्यक्ति के आंतरिक ऊर्जा चक्र को संतुलित करने में सहायक होते हैं।

मंगल को "भूमि पुत्र" भी कहा जाता है, इसलिए मिट्टी से जुड़े उपाय भी विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करना या भूमि से जुड़े कार्यों में भाग लेना मंगल दोष को शांत करने में सहायक होता है। यह उपाय व्यक्ति को स्थिरता और धैर्य प्रदान करता है।

व्रत और संयम का भी इस दोष के निवारण में महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग वैवाहिक समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें कम से कम 21 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम को हनुमान जी को फलाहार अर्पित करना चाहिए। यह अनुशासन व्यक्ति के भीतर आत्मसंयम और सकारात्मक सोच को विकसित करता है।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल दोष केवल एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर के असंतुलन को भी दर्शाता है। जब व्यक्ति में क्रोध, अहंकार, अधैर्य और आक्रामकता बढ़ जाती है, तो यह मंगल के नकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए बाहरी उपायों के साथ-साथ आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। जब मन शांत होता है और विचार सकारात्मक होते हैं, तब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भी स्वतः कम होने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि जीवनशैली में सुधार पर भी जोर देते हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि मंगल दोष कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन लाने की आवश्यकता है। मंगलनाथ मंदिर में होने वाली भात पूजा इस दिशा में एक शक्तिशाली माध्यम है, जो व्यक्ति को न केवल बाहरी समस्याओं से राहत दिलाती है, बल्कि उसे आंतरिक रूप से भी मजबूत बनाती है।

यदि श्रद्धा, विश्वास और सही उपायों के साथ प्रयास किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति मंगल दोष के प्रभाव को कम कर सकता है और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। यही इस परंपरा का मूल संदेश है—आस्था, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाना।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

शहरों का होगा सर्वांगीण विकास, प्रधानमंत्री के करकमलों से रचा जाएगा नया इतिहास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च को गुजरात के शहरों को देंगे 5295 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात

अकेले अहमदाबाद में ही 4640 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास

गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का 'अपने घर' का सपना होगा साकार : हजारों परिवारों को मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान

ऐतिहासिक नगरी वडनगर में हेरिटेज टाउन और सड़क सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का होगा लोकार्पण

गांधीनगर : गुजरात के शहरी विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च को अपने गुजरात दौरे के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनता की सुख-सुविधा में वृद्धि करने वाले तथा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विभिन्न विकास-उन्मुख परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शहरी विकास को बढ़ावा देने वाले राज्य के कुल 5295.54 करोड़ रुपए के 44 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 3427.14 करोड़ रुपए के 26 कार्यों का शिलान्यास और 1868.40 करोड़ रुपए के 18 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

इसके अंतर्गत, सबसे अधिक अहमदाबाद महानगर पालिका की 4640.12 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं, जबकि गांधीनगर महानगर पालिका की 304.82 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं, गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण की 272.86 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं तथा गुजरात अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 77.74 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐतिहासिक नगरी वडनगर की विरासत को संरक्षित रखने और पर्यटन को गति देने के लिए 34.45 करोड़ रुपए के खर्च से 'हेरिटेज टाउन शहरी विकास और सड़क सौंदर्यीकरण' प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाटकेश्वर मंदिर और संगीत संग्रहालय जैसे मुख्य स्थलों पर आधुनिक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड लाइटिंग, सेंड स्टोन साइनेज और कलात्मक कृतियों से सौंदर्यीकरण किया गया है।

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री पाटण में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। पाटण शहर के लोगों की सुविधा के लिए 43.29 करोड़ रुपए की लागत से फाटक नंबर 41-ए (एलसी-41ए) पर 898 मीटर लंबा श्री-लेग रेलवे ओवरब्रिज तैयार किया गया है, जो यातायात की समस्या को दूर कर लगभग दो लाख लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा।

इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के मकानों का लोकार्पण करेंगे, जिससे हजारों परिवारों का 'अपने घर' का सपना साकार होगा। साथ ही साथ, अहमदाबाद के नए क्षेत्रों में ड्रेनेज और अन्य ढांचागत सुविधाओं की बड़ी परियोजनाएं आगामी समय में शहर का कायापलट करेंगी।

प्रधानमंत्री अहमदाबाद मनपा के इन विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

1. खारीकट कैनाल डेवलपमेंट (पैकेज 1,2,3) – लोकार्पण – 811.27 करोड़ रुपए
2. निकोल-कठवाड़ा (टीपी-111) में 1100 ईडब्ल्यूएस आवास - लोकार्पण – 77.50 करोड़ रुपए
3. चिलोड़ा-नरोड़ा (टीपी-99) में 1017 ईडब्ल्यूएस आवास – लोकार्पण – 75.35 करोड़ रुपए
4. नरोड़ा-मुठिया (टीपी-71) में 470 ईडब्ल्यूएस आवास – लोकार्पण – 56 करोड़ रुपए
5. अमराईवाड़ी स्लम क्वार्टर्स में 672 आवास (पीपीपी) – लोकार्पण – 54.92 करोड़ रुपए
6. गोता (टीपी-33) में 448 ईडब्ल्यूएस आवास – लोकार्पण – 54.75 करोड़ रुपए
7. असारवा नॉर्थ (टीपी-30) पतरावाळी स्लम में 576 आवास – लोकार्पण – 47.93 करोड़ रुपए
8. हंसपुरा-नरोड़ा (टीपी-121) में 299 ईडब्ल्यूएस आवास – लोकार्पण – 35.59 करोड़ रुपए
9. वस्त्राल वार्ड (टीपी-114) में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण – लोकार्पण – 61.67 करोड़ रुपए

10 गोता-गोधावी कैनाल का आरसीसी बॉक्स कैनाल में रूपांतरण – लोकार्पण – 131.97 करोड़ रुपए

11. आकाश दर्शन सोसायटी के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन – लोकार्पण – 25.08 करोड़ रुपए

12. दुधेश्वर वाटर वर्क्स में 20 मिलियन लीटर का टैंक – लोकार्पण – 31.07 करोड़ रुपए

13. भाड़ज (टीपी-406) में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन – लोकार्पण – 47.40 करोड़ रुपए

14. खारीकट कैनाल फेज-2 (रोपड़ा तालाब से खारी नदी तक) – शिलान्यास – 1061.43 करोड़ रुपए

15. बीआरटीएस और एएमटीएस के लिए आईटीएमएस सिस्टम प्रोजेक्ट 2.0 – शिलान्यास – 467 करोड़ रुपए

16. नारोल सर्कल से नरोड़ा पाटिया तक 14 किमी रोड़ डेवलपमेंट – शिलान्यास – 255.35 करोड़ रुपए

17. काजीमिया नो टेकरो (टीपी-3) में 728 आवास (पीपीपी) – शिलान्यास – 105.02 करोड़ रुपए

18. भागुभाई नी चाली (टीपी-3) में 595 आवास (पीपीपी) – शिलान्यास – 73.59 करोड़ रुपए

19 वटवा आउटफील्ड (टीपी-58) में 350 एलआईजी आवास – शिलान्यास – 66.18 करोड़ रुपए

20 नरोड़ा-हंसपुरा (टीपी-121) में 160 एलआईजी आवास – शिलान्यास – 38.80 करोड़ रुपए

21. वस्त्राल वार्ड में 1600 एमएम ड्रेनेज लाइन (माइक्रो टनलिंग) – शिलान्यास – 31.24 करोड़ रुपए

22 नरोड़ा वार्ड (टीपी-75) में नया ऑडिटोरियम – शिलान्यास – 86.29 करोड़ रुपए

23. रास्का में अतिरिक्त 100 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट – शिलान्यास – 79.48 करोड़ रुपए

24 सीजी रोड में एडवांस फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी – शिलान्यास – 37.22 करोड़ रुपए

25 सुभाष ब्रिज का नवनिर्माण (4 लेन ब्रिज और 2 लेन ब्रिज) – शिलान्यास – 236 करोड़ रुपए

26. वेस्ट जोन में थिमैटिक प्रिसिंक्ट पैकेज-1 के विभिन्न रोड – शिलान्यास – 282.82 करोड़ रुपए

27. लोटस पार्क डेवलपमेंट (घाटलोडिया तालाब) – शिलान्यास – 128.85 करोड़ रुपए

28. नॉर्थ-वेस्ट जोन (टीपी-56, 151-ए आदि) में ड्रेनेज नेटवर्क – शिलान्यास – 42.93 करोड़ रुपए

29 नॉर्थ-वेस्ट जोन (टीपी-54, 55, 228 आदि) में ड्रेनेज नेटवर्क – शिलान्यास – 40.47 करोड़ रुपए

30 नॉर्थ-वेस्ट जोन (टीपी-40, 41, 53-ए आदि) में ड्रेनेज नेटवर्क – शिलान्यास – 28.42 करोड़ रुपए

31 हेबतपुर-थलतेज क्षेत्र में तालाबों को जोड़ने का नेटवर्क – शिलान्यास – 27.85 करोड़ रुपए

32 ओलंपिक-2036 के अंतर्गत नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के निकट वाटर लाइन शिफ्टिंग – शिलान्यास – 40.68 करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री गांधीनगर महानगर पालिका और गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण के इन विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

1 वासणा-हड़मतिया (टीपी-09) में 624 ईडब्ल्यूएस-2 आवासों का निर्माण – लोकार्पण – 80.50 करोड़ रुपए

2 वासणा-हड़मतिया (टीपी-09) में 1352 ईडब्ल्यूएस-2 आवासों का निर्माण – लोकार्पण – 165.54 करोड़ रुपए

3 मोटा चिलोड़ा (टीपी-17) में ड्रेनेज नेटवर्क और 7.0 एमएलडी एसटीपी – शिलान्यास – 26.82 करोड़ रुपए

4 जीएमसी क्षेत्र (टीपी-06) में वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण – शिलान्यास – 25.61 करोड़ रुपए

5 सेक्टर-11 बिजनेस कॉरिडोर रोड डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण – शिलान्यास – 25.53 करोड़ रुपए

6 रांधेजा में 4 तालाबों को जोड़ने और स्टॉर्म वाटर लाइन – शिलान्यास – 25.02 करोड़ रुपए

7 कोबा, रायसण, रांदेसण क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर लाइन – शिलान्यास – 59.48 करोड़ रुपए

8 टीपी-29 से अडालज टीएसपीएस तक 1800 एमएम ड्रेनेज ट्रंक मेन – शिलान्यास – 62.15 करोड़ रुपए

9 कुडासण, रायसण, रांदेसण, सरगासण सहित अन्य गांवों में नए रोड – शिलान्यास 72.91 करोड़ रुपए

10 पेथापुर में 15 एमएलडी एसटीपी का निर्माण – लोकार्पण – 34.12 करोड़ रुपए

राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने इन सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री का यह दौरा गुजरात के शहरी बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में क महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

10 जून से पोरबंदर–दादर दैनिक सौराष्ट्र एक्सप्रेस की कोच संरचना में परिवर्तन

यात्रियों की बढ़ती मांग एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 19016/19015 पोरबंदर–दादर–पोरबंदर दैनिक सौराष्ट्र एक्सप्रेस की कोच संरचना में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रही सेकंड एसी कम थर्ड एसी (2AC cum 3AC) कोच के स्थान पर अब अलग-अलग एक सेकंड एसी (2AC) तथा एक थर्ड एसी (3AC) कोच लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा एवं अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

यह संशोधित कोच संरचना निम्नानुसार प्रभावी होगी:

- ट्रेन संख्या 19016 पोरबंदर–दादर दैनिक सौराष्ट्र एक्सप्रेस में 10 जून, 2026 से
- ट्रेन संख्या 19015 दादर–पोरबंदर दैनिक सौराष्ट्र एक्सप्रेस में 13 जून, 2026 से
- यात्रियों अपनी यात्रा से पूर्व ट्रेनों के संचालन एवं कोच संरचना की अद्यतन जानकारी NTES App, Indian Railways की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

अविरत गुजरात, विकसित गुजरात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साणंद और नरोड़ा जीआईडीसी की 271 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे

साणंद में बारिश में जलजमाव की समस्या का स्थायी हल : 244 करोड़ रुपए के खर्च से आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट पूर्ण

इस प्रोजेक्ट से साणंद औद्योगिक क्षेत्र अब 'जीरो वाटर लॉगिंग' जोन बनेगा

नरोड़ा औद्योगिक क्षेत्र का 27.20 करोड़ रुपए के खर्च से नवीनीकरण : आधुनिक ढांचागत सुविधाओं से उद्योगों को मिलेगा बूस्ट

प्रधानमंत्री 31 मार्च को गुजरात की औद्योगिक क्षमता को बल देने वाली परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे

गांधीनगर : 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च, 2026 को गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे अहमदाबाद के साणंद शहर से गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा पूरी की गई 271.20 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

अहमदाबाद जिले के साणंद में लगभग 2056 हेक्टेयर में फैला औद्योगिक क्षेत्र आज सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और फार्मास्युटिकल्स जैसे हाई-टेक उद्योगों का हब बन गया है। यहां 1150 से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं। मानसून के दिनों में इस क्षेत्र में होने वाली जमजमाव की गंभीर समस्या के स्थायी हल के लिए जीआईडीसी ने दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरे किए हैं।

इनमें पूर्व और पश्चिम ड्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के दोनों ओर 18.71 किमी लंबी आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई गई है, जो आंतरिक और ऊपरी क्षेत्र के पानी की निकासी करेगी। इसके अलावा, साणंद-वीरमगाम हाईवे के मुख्य प्रवेशद्वारों के पास 18.35 किमी लंबी ड्रेन सिस्टम तैयार किया गया है।

मार्च-2026 में पूरे हुए इस प्रोजेक्ट से साणंद औद्योगिक क्षेत्र अब 'जीरो वाटर लॉगिंग' जोन बनने की ओर आगे बढ़ रहा है।

1963 में स्थापित राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक बसाहटों में से एक नरोड़ा औद्योगिक क्षेत्र को भी राज्य सरकार की 'असिस्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर (एआईआई)' योजना के तहत नया कलेवर दिया गया है। यहां 27.20 करोड़ रुपए के खर्च से विभिन्न कार्य पूरे किए गए हैं। इसके अंतर्गत, आंतरिक सड़कों का मजबूतीकरण और विस्तार, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और प्राकृतिक नाले की लाइनिंग, 1.19 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में पेवर ब्लॉक, फुटपाथ और पार्किंग की सुविधा तथा नई स्ट्रीट लाइट्स, हाई-मास्ट लाइट्स, सिक्योरिटी केबिन और टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण किया गया है।

इन परियोजनाओं के लोकार्पण से साणंद और नरोड़ा के हजारों लघु और बड़े उद्योगों को सीधा फायदा होगा। आधुनिक ड्रेन सिस्टम, स्मार्ट वाटर मीटर, सीसीटीवी सर्विलांस और सड़कों के मजबूतीकरण के कारण माल-सामान की आवाजाही आसान हो जाएगी और गुजरात वैश्विक निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बन जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और अग्रणी उद्योगपति मौजूद रहेंगे।

गिफ्ट सिटी : भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल और आईटी हब

आज गिफ्ट सिटी में 1150 से अधिक आईएफएससीए-रजिस्टर्ड संस्थान संचालित

गिफ्ट सिटी में बैंकिंग क्षेत्र 106 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, पूंजी बाजार 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

गांधीनगर, 28 मार्च : गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) भारत के पहले संपूर्ण रूप से संचालित वैश्विक फाइनेंशियल और आईटी हब के रूप में उभरा है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में देश को अग्रिम कतार में खड़ा रखता है।

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्थापित की गई गिफ्ट सिटी आज एक समृद्ध, नीति-संचालित और वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक वित्तीय केंद्र में परिवर्तित हो गई है।

प्रारंभ से ही, गिफ्ट सिटी की परिकल्पना एक विश्वस्तरीय फाइनेंस और आईटी जोन के रूप में की गई थी। एक ऐसा वित्तीय केंद्र जो न केवल भारत को, बल्कि पूरी दुनिया को सेवाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक ऐसे एकीकृत इकोसिस्टम की नींव रखी गई, जो वित्तीय सेवाओं, टेक्नोलॉजी, विनियामक सुगमता और ढांचागत सुविधाओं को एक ही अधिकार क्षेत्र के भीतर जोड़ता है। उनका विजन अब एक जीवंत केंद्र मंक परिवर्तित हो गया है, जो स्थापित वैश्विक वित्तीय केंद्रों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करता है।

आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गिफ्ट सिटी की क्षितिजों का विस्तार हो रहा है, और वे उसी प्रतिबद्धता के साथ गिफ्ट सिटी की निरंतरता, विस्तार और तेज विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में गिफ्ट सिटी ने नई ऊंचाइयां छुई हैं, जो भारत के आर्थिक विकास के प्रेरक बल के रूप में गुजरात की प्रतिष्ठा को मजबूत बनाती है।

आज गिफ्ट सिटी में 1150 से अधिक आईएफएससीए-रजिस्टर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में पंजीकृत) संस्थान कार्यरत हैं। गिफ्ट सिटी में बैंकिंग

क्षेत्रों का भी उल्लेखनीय विकास हुआ है, जो 106 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह 2020 की तुलना में लगभग सात गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, पूंजी बाजार (कैपिटल मार्केट) भी 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और हर महीने एक्सचेंज टर्नओवर लगातार 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, 80 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के साथ 349 फंड्स शुरू किए गए हैं, जो वैश्विक पूंजी बाजारों में भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत बनाते हैं।

गिफ्ट सिटी का विकास केवल वित्तीय गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक गिफ्ट सिटी में वर्ष 2030 तक 1,00,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिसमें कमर्शियल (व्यापारिक), रेजिडेंशियल (रिहायशी) और इंस्टीट्यूशनल (संस्थागत) निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का बड़ा योगदान होगा।

इसके साथ ही, गिफ्ट सिटी में एक मजबूत सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण किया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्कूल, डेस्टिनेशन मॉल, सेंट्रल पार्क और स्पोर्ट्स एरिना आदि शामिल हैं। गिफ्ट सिटी में रहने वाले लोगों और काम करने वाले पेशेवरों, दोनों के लिए 'लिव, वर्क, थ्राइव' यानी जिएं, काम करें और समृद्ध बनें के मंत्र के साथ इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है।

गिफ्ट सिटी में अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में पहली बार यहां अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल स्थापित की गई है। इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और ऑटोमैटेड वेस्ट कलेक्शन के जरिए कुशल और टिकाऊ परिचालन सुनिश्चित किए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर, गिफ्ट सिटी भारत के अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल गेटवे के रूप में काम करता है, जिसकी पहुंच दावोस में विश्व आर्थिक मंच जैसे कार्यक्रमों और मिलान, ज्यूरिक, हांगकांग, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों तक है। भारत में, यह बैंकिंग फोरम (100 से अधिक संस्थानों के साथ), वाइब्रेंट गुजरात, आईजीएफ मुंबई और रिइंश्योरेंस समिट के साथ समन्वय बनाकर स्थानीय और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क को एक साथ लाता है।

गिफ्ट सिटी में एक ही छत के नीचे विभिन्न वित्तीय सेवाएं मिलती हैं, जिनमें पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, विमान और जहाज लीजिंग सेवाएं, फिनटेक, जीसीसी और वैश्विक यूनिवर्सिटियों के साथ साझेदारी शामिल हैं। यह 37 से अधिक बैंकों, 65 से अधिक बीमा कंपनियों और 35 से अधिक एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों के साथ एक उच्च-मूल्य वाली वित्तीय सेवाओं के एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और वैश्विक वित्तीय इकोसिस्टम में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने में सहयोग कर रहा है।

गिफ्ट सिटी की शुरुआत श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में इसका लगातार विकास किया गया है। यह भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के रणनीतिक और दीर्घकालिक विजन को प्रतिबिंबित करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 मार्च को गुजरात में 891 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे

खेडब्रह्मा से हिंमतनगर होकर अहमदाबाद (असारवा) तक की नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 मार्च मंगलवार को गुजरात की एक दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे राज्य के नागरिकों को भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के 891 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की भेंट देंगे। कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने, आर्थिक गतिविधियों को गति देने और यात्रियों की परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में वाव-थराद से इन प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि रेलवे के ये प्रोजेक्ट्स गुजरात में रेल अवसंरचना के आधुनिकीकरण एवं क्षेत्रीय विकास को वेग देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित होने वाले रेलवे प्रोजेक्ट्स

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हिंमतनगर से खेडब्रह्मा तक 55 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिसका 482 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। इसके जरिये साबरकाँठा जिले में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जो त्वरित एवं पोषक दर पर यात्रा सुनिश्चित करेगा और इस प्रोजेक्ट से अहमदाबाद को उदयपुर के साथ सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। अनुमान है कि इससे स्वास्थ्य शुश्रुषा तथा शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुँच में वृद्धि होगी और साथ ही साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इसके अलावा; 257 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कानालुस-जामनगर डबलिंग प्रोजेक्ट (27 किलोमीटर) अंतर्गत अतिरिक्त रेलवे लाइन तथा गांधीधाम-आदिपुर मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट (11 किलोमीटर) का भी प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। इन परियोजनाओं से ट्रेनों का आवागमन अधिक तेज एवं सुगम बनेगा। साथ ही साथ; माल-सामान की आवाजाही अधिक कार्यक्षम रूप से होगी और दीनदयाल पोर्टल सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ये परियोजनाएँ स्थानीय पर्यटन विकास में भी योगदान देंगी।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खेडब्रह्मा से अहमदाबाद तक की ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो वाया हिंमतनगर होकर चलेगी। यह ट्रेन शुरू होने से इस क्षेत्र में नागरिकों के लिए यात्रा अधिक तेज एवं सुगम बनेगी और स्थानीय आर्थिक विकास को वेग मिलेगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार भारतीय रेलवे को आधुनिक तथा अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर नागरिकों के यात्रा अनुभव को समृद्ध बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इन पहलों से समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनेगी।

नई उड़ान का दौर: जेवर से उठी विकास की ऐतिहासिक शुरुआत

उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी में एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया, जब नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं था, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर थी, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोएडा के जेवर क्षेत्र में बना यह एयरपोर्ट आज देश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल हो चुका है, जिसने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास को नई दिशा देने का काम किया है।

करीब 5,000 हेक्टेयर में फैला यह विशाल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हो रहा है। इसका निर्माण चार चरणों में किया जाना है, जिसमें पहले चरण पर लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ की लागत आई है और यह अब संचालन के लिए तैयार हो चुका है। पहले चरण में एक रनवे तैयार किया गया है, जबकि पूरी परियोजना पूरी होने के बाद यहां कुल छह रनवे होंगे। शुरुआती चरण में यह एयरपोर्ट लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालने में सक्षम होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 से 8 करोड़ यात्रियों तक किया जा सकता है।

यह एयरपोर्ट भारत का एक प्रमुख ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक और मल्टी-फेज विकास योजना के साथ तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर के मौजूदा एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को गति देना है। इसके साथ ही यह क्षेत्रीय रोजगार, व्यापार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगा।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

नॉन फेयर रेवन्यू (NFR) के माध्यम से ई–नीलामी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक–रतलाम मंडल– पश्चिम रेलवे ने नॉन फेयर रेवन्यू (NFR) के माध्यम से ई–नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को www.ireps.gov.in के (ई–ऑक्शन लीजिंग) पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है। **केटलॉग सं.–** MSS-RTM-63. **अनुबंध का प्रकार :** Non Fare Revenue (NFR). **लॉट न. :** MSS-RTM-INDB-GBTPA-80-26-2, (Misc.-Static-Services - Glow ball tower with Promotional Audio), **अनुबंध की अवधि : 05** Years. ई–नीलामी की तिथि और समय लॉट के लिए ई–नीलामी **दिनांक 11.04.2026 को 12:00 बजे प्रारंभ होगी।** प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। IREPS के ई–ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

SNP-524

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट में 1010 आवासों सहित 751 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- ‘ईज ऑफ लिविंग’ की मंशा के साथ आगे बढ़ते राजकोट को 751.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट मिली
- राज्य सरकार योजनाबद्ध विकास कार्यों को तत्काल मंजूरी देती है
- विकास कार्यों के लिए गुजरात का वित्तीय प्रबंधन देश भर में प्रथम

....

प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

- राजकोट महानगर पालिका द्वारा गत 15 दिनों में 1100 करोड़ रुपए के कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास का रिकॉर्ड
- समान नागरिक संहिता विधेयक लाने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य

- **भविष्य के राजकोट के लिए 543 करोड़ रुपए के 40 नए प्रोजेक्ट की नींव रखी गई**
- **सड़क, ड्रेनेज और रोशनी के कार्यों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई गति**
- **लोगों की सुख-सुविधा के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर : शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला**

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को राजकोट में महानगर पालिका के 751.20 करोड़ रुपए के 45 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 119.05 करोड़ रुपए के खर्च से नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस-2 प्रकार के आवासों का लोकार्पण करके मुख्यमंत्री ने 1010 परिवारों को आधुनिक सुविधा युक्त ‘अपने घर’ की भेंट दी है। इसके साथ ही, 9.78 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और नए व्हीकल टेस्ट ट्रैक का भी लोकार्पण किया गया।

राजकोट में प्रमुख स्वामी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘अर्न वेल, लिव वेल’ की मंशा के साथ आगे बढ़ रहे राजकोट को आज 751.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट मिली है। गुजरात राज्य का विकास मॉडल और विकास कार्यों के लिए गुजरात का वित्तीय प्रबंधन देश भर में अव्वल स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नागरिकों के कल्याण के लिए जरूरी एक भी विकास कार्य बाकी नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार योजनाबद्ध विकास कार्यों को कभी नामंजूर नहीं करती, बल्कि ऐसे कार्यों की योजना को तत्काल मंजूरी दी जाती है। इस अवसर पर उन्होंने निर्माणाधीन विकास कार्यों में गुणवत्ता को बनाए रखने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प दिया है, तब ‘विकसित भारत’ के लिए देश के आम नागरिक को मुख्यधारा में शामिल करना आवश्यक है, और इसके लिए ही राज्य में ‘वाइब्रेंट गुजरात समिट’ को रीजनल यानी क्षेत्रीय स्तर पर ले जाया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बतौर सरकार के मुखिया अपने शासनकाल के 8931 दिन पूरे करने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा की शुरुआत राजकोट से हुई थी और राजकोट से शुरू हुआ यह रिकॉर्ड आज लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के कल्याण के मंत्र के साथ कार्यरत श्री नरेन्द्र मोदी गरीबों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए हैं। आज पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए और डीजल में एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। जब कभी दुनिया में संकट पैदा हुआ है, तब श्री नरेन्द्र मोदी ने हिम्मतपूर्वक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि देश के प्रत्येक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के पास ‘अपना घर’ हो। गुजरात सरकार इस सपने को साकार करने के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रही है। आज राजकोट में आवास योजना के जरिए एक हजार से अधिक परिवारों को उनके सपनों का घर मिल रहा है।

इस अवसर पर राजकोट जिला प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने आज के कार्यक्रम को जनकल्याण का ऐतिहासिक अवसर करार देते हुए कहा कि राजकोट महानगर पालिका द्वारा पिछले 15 दिनों में ही 1100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है।

हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा विधानसभा में पेश किए गए और बहुमत से पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के संबंध में श्री वाघाणी ने कहा कि यूसीसी विधेयक मुख्यमंत्री का ‘दिल’ है। गुजरात समूचे देश में यह विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य है। इसके साथ ही, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि गुजरात सरकार जनता के हित के लिए जरूरी सभी निर्णय करती रहेगी।

उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र से विकास की धारा गुजरात भर में प्रवाहित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अविरत विकास यात्रा के परिणामस्वरूप हुआ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। राजकोट महानगर पालिका के निरंतर प्रयासों के चलते आज राजकोट के हर कोने का विकास हुआ है। शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने कहा कि आज राजकोट में शहरी विकास विभाग के 543 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 207 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। उन्होंने इसके लिए नागरिकों को बधाई दी।

श्रीमती वाघेला ने कहा कि उत्सवप्रिय और रंगीला राजकोट अब विकास कार्यों में भी आगे बढ़ रहा है। ड्रेनेज, पानी और सड़कों के विकास कार्यों से आगे बढ़कर राज्य सरकार ने गरीबों की वेदना को समझते हुए आवासों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए लगातार तत्पर रहेगी और आगामी दिनों में राजकोट विकास के मामले में मॉडल सिटी बनेगा। इस अवसर पर सांसद श्री परशोत्तमभाई रूपाला ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात का सर्वांगीण विकास हुआ है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशा-निर्देश में यह वाइब्रेंट समिट अब क्षेत्रीय स्तर पर पहुंच गई है। यह गर्व की बात है कि राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन हुआ और इसे सफलता मिली।

अफवाहों के बीच भरोसे की बात: देश में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक स्तर पर उठ रही चिंताओं के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर फैल रही आशंकाओं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। कंपनी ने साफ शब्दों में कहा है कि देश में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य और संतुलित बनी हुई है।

हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच हालात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी है। इन परिस्थितियों का असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ देखने को मिली, जिससे लोगों के मन में ईंधन संकट की आशंका और गहरा गई।

इन सभी आशंकाओं को दूर करते हुए HPCL ने कहा कि देशभर में उसके सभी फ्यूल स्टेशन सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और कहीं भी सप्लाई में कोई बाधा नहीं आई है। कंपनी के अनुसार, भारत की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, बल्कि भविष्य की आपूर्ति को लेकर भी कोई खतरा नहीं है।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का मजबूत रिफाइनिंग नेटवर्क लगातार ईंधन उत्पादन और वितरण को बनाए हुए है। देश में कई अत्याधुनिक रिफाइनरियां हैं, जो कच्चे तेल को प्रोसेस कर बड़े पैमाने पर ईंधन तैयार करती हैं। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर चाहे जितनी भी अनिश्चितता क्यों न हो, भारत अपनी आंतरिक जरूरतों को संतुलित ढंग से पूरा करने में सक्षम है। HPCL ने पेट्रोल पंपों पर देखी गई भीड़ को लेकर कहा कि यह स्थिति वास्तविक कमी के कारण नहीं, बल्कि गलत जानकारी यानी मिसइन्फॉर्मेशन के चलते उत्पन्न हुई। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैली अफवाहों ने लोगों को चिंतित कर दिया, जिसके चलते उन्होंने जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदना शुरू कर दिया।

पश्चिम रेलवे चलाएगी पाँच स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष किराये पर पाँच स्पेशल ट्रेनें चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 02200/02199 बांद्रा टर्मिनस–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 02200 बांद्रा टर्मिनस – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल प्रत्येक शनिवार 05:10 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान कर अगले दिन 05:00 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार 16:50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 16:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 02 अप्रैल, 2026 से 09 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, बियावरा राजगढ़, चाचौड़ा बीनागंज, रुठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, डबरा एवं दतिया स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 04126/04125 बांद्रा टर्मिनस – सूबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 04126 बांद्रा टर्मिनस – सूबेदारगंज स्पेशल प्रत्येक मंगलवार 11:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 17:00 बजे सूबेदारगंज पहुँचेगी। यह ट्रेन 07 अप्रैल, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04125 सूबेदारगंज – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार 05:20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 09:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, आगरा इडगाह, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी एवं फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 05184/05183 बांद्रा टर्मिनस – आजमगढ़ सुपरफास्ट स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 05184 बांद्रा टर्मिनस – आजमगढ़ स्पेशल प्रत्येक सोमवार 10:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:10 बजे आजमगढ़ पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05183 आजमगढ़ – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक शनिवार 23:15 बजे प्रस्थान कर सोमवार को 08:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड, बनारस, औंरीहर, मऊ एवं मोहम्मदाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 05034/05033 बांद्रा टर्मिनस – गोमती नगर स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 05034 बांद्रा टर्मिनस – गोमती नगर स्पेशल प्रत्येक मंगलवार 23:00 बजे प्रस्थान कर गुरुवार को 07:45 बजे गोमती नगर पहुँचेगी। यह ट्रेन 07 अप्रैल, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05033 गोमती नगर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार 14:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 05018/05017 वलसाड – मऊ स्पेशल [30 फेरे]

ट्रेन संख्या 05018 वलसाड – मऊ स्पेशल प्रत्येक रविवार 15:10 बजे वलसाड से प्रस्थान कर मंगलवार को 00:45 बजे मऊ पहुँचेगी। यह ट्रेन 05 अप्रैल, 2026 से 12 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05017 मऊ – वलसाड स्पेशल प्रत्येक शनिवार 03:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 12:35 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सलेमपुर एवं बेल्थरा रोड स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 02200, 04126, 05184, 05034 एवं 05018 की बुकिंग 31.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में गुजरात की ऐतिहासिक सफलता

- **कच्छ में एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के चूजे का जन्म-आगमन : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया**
- **‘ऑपरेशन एग ट्रांसफर’ के अंतर्गत राजस्थान के ब्रीडिंग सेंटर से गोडावण के एक उर्वर अंडे को 19 घंटे की सड़क यात्रा के जरिए पोर्टेबल इनक्यूबेटर में सुरक्षित रूप से कच्छ लाया गया**
- **यह सफलता ‘जम्पस्टार्ट एप्रोच’ नामक नवाचारपूर्ण संरक्षण प्रयास के माध्यम से संभव हुई**

गांधीनगर : गुजरात और राजस्थान के वन विभागों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) के संयुक्त प्रयासों से वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता मिली है।

गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि कच्छ के अबडासा क्षेत्र में एक दशक के लंबे अंतराल के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी- गोडावण) के चूजे का जन्म हुआ है, जो हम सभी के लिए गर्व का क्षण है।

वन मंत्री श्री मोढवाडिया ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात वन विभाग ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वाइल्ड लाइफ डिविजन के अधिकारियों के कार्यों की प्रशंसा की और इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को बधाई दी।

इस सफलता के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात और राजस्थान तथा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) के संयुक्त प्रयासों की सराहना की और एक्स पर इस बारे में जानकारी देते हुए सभी को बधाई दी।

वन मंत्री श्री मोढवाडिया ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि यह सफलता ‘जम्पस्टार्ट एप्रोच’ नामक नवाचारपूर्ण संरक्षण प्रयासों के माध्यम से संभव हुई है।

पृष्ठभूमि और प्रोजेक्ट जीआईबी

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2011 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी-गोडावण) पक्षी को उसके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने की परिकल्पना के अनुरूप वर्ष 2016 में ‘प्रोजेक्ट जीआईबी’ शुरू किया गया।

नतीजतन, राजस्थान के सम और रामदेवरा में स्थापित ब्रीडिंग सेंटरों में पक्षियों की संख्या बढ़कर अब 73 तक पहुंच गई है।

कैसे मिली सफलता, (ऑपरेशन एग ट्रांसफर)

कच्छ में जीआईबी (गोडावण) की आबादी में नर पक्षियों की अनुपस्थिति के कारण मादा गोडावण अंडे तो देती थी, लेकिन वे निष्फल (इन्फर्टाइल) रहते थे। इस समस्या के समाधान के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया गया।

ट्रांस-स्टेट यात्रा

राजस्थान के ब्रीडिंग सेंटर से जीआईबी (गोडावण) का एक उर्वर अंडा लिया गया। इस अंडे को 19 घंटे की सड़क यात्रा के माध्यम से पोर्टेबल इनक्यूबेटर में सुरक्षित रूप से कच्छ लाया गया।

नेस्ट रिप्लेसमेंट

22 मार्च को कच्छ की मादा जीआईबी (गोडावण) के घोंसले में निष्फल अंडे के बदले इस उर्वर अंडे को रखा गया। मादा गोडावण ने इस अंडे को प्राकृतिक रूप से सेया और 26 मार्च को उससे स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ।

भविष्य की योजना

फिलहाल फील्ड मॉनिटरिंग टीम मादा गोडावण और उसके बच्चे की लगातार निगरानी कर रही है।

वन मंत्री श्री मोढवाडिया ने कहा कि यह वैज्ञानिकों, वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक गौरव का क्षण है, जो भारत के वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को और मजबूत करता है।

खेड़ब्रह्मा - वडाली रेलखंड पर टेस्ट टिकट जारी,नई रेल सेवा शुभारंभ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

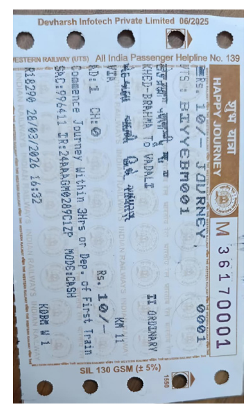

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा अवगत कराया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिनांक 31 मार्च, 2026 को गुजरात राज्य में 891 करोड़ लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत खेड़ब्रह्मा – हिम्मतनगर – अहमदाबाद (असारवा) के मध्य नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ तथा खेड़ब्रह्मा – हिम्मतनगर रेलखंड का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इसी क्रम में, आज दिनांक 28 मार्च, 2026 को खेड़ब्रह्मा से वडाली तक का सफलतापूर्वक 10 मूल्य का टेस्ट टिकट जारी कर परिचालन की परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण की गई, जो इस नई रेल सेवा के शुभारंभ की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परीक्षण यात्रियों के लिए टिकटिंग व्यवस्था, परिचालन प्रणाली एवं सुविधाओं की तैयारियों का सफल आकलन दर्शाता है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को नई ट्रेन सेवा के शुभारंभ से पूर्व, स्थानीय सांसद एवं विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण 11वीं शताब्दी के प्राचीन ब्रह्मा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे तथा तत्पश्चात रेलवे स्टेशन पर भी विधिवत पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खेड़ब्रह्मा, उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित एक प्राचीन एवं पवित्र धार्मिक नगरी है, जिसे ब्रह्माक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान भगवान ब्रह्मा, ऋषि भृगु एवं माँ अंबिका से जुड़ी आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां स्थित प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर, जिसे स्थानीय रूप से “नाना अंबाजी” कहा जाता है, क्षेत्र की ग्रामदेवता के रूप में पूजित माँ अंबिका को समर्पित है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता, आध्यात्मिक महत्व तथा समृद्ध आदिवासी संस्कृति के कारण विशेष पहचान रखता है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक मारु-गुर्जर शैली में निर्मित है, जिसमें नक्काशीदार स्तंभ, गर्भगृह एवं शांत परिसर दर्शनीय हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र वह स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था तथा देवी अंबिका ने असुरों का संहार कर साधुओं की रक्षा की थी। तभी से यह स्थल एक प्रमुख शक्ति उपासना केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने बताया कि यह नई रेल सेवा न केवल क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति देगी।

आधुनिक को-वर्किंग सुविधा के साथ यात्रियों के प्रतीक्षा अनुभव को मिला नया आयाम

वडोदरा स्टेशन पर ‘एयरपोर्ट जैसा अनुभव’, गुजरात के पहले डिजिटल लाउंज का माननीय सांसद डॉ. हेमांग जोशी द्वारा उद्घाटन

यात्रियों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा वडोदरा रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लाउंज / को-वर्किंग स्पेस विकसित किया गया है, जिसका आज माननीय सांसद डॉ. हेमांग जोशी एवं माननीय विधायक श्री केयूर रोकडिया द्वारा उद्घाटन किया गया।

यह सुविधा गुजरात में रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह की पहली तथा भारतीय रेल पर मुंबई सेंट्रल के बाद दूसरी है, जो वडोदरा स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं के नए स्तर पर ले जाती है।

इस अवसर पर माननीय सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने बताया कि वडोदरा रेलवे स्टेशन पर आज ‘विकसित वडोदरा से विकसित भारत’ की झलक दिखाई देती है। जैसे एयरपोर्ट के अंदर VVIP लाउंज होता है, वैसी ही सुविधा अब वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। यात्री अब एक ही स्थान पर मीटिंग, चाय-नाश्ता और विश्राम जैसी सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही, बहुत ही किफायती दरों पर शॉवर और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह वडोदरा के लिए एक महत्वपूर्ण और गर्व का कदम है।

माननीय विधायक श्री केयूर रोकडिया ने कहा कि वास्तव में, पहली बार वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी, नए फीचर्स का समावेश तथा कार्गो के लिए अलग डेक जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

इस अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने बताया कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में वडोदरा स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए इसे पश्चिम रेलवे के सबसे स्वच्छ स्टेशनों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में, ‘उत्तम स्वच्छ स्टेशन’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए, एनएफआर पहल के अंतर्गत इस डिजिटल लाउंज की योजना बनाई गई है। वडोदरा के बरगद वृक्ष थीम पर आधारित यह लाउंज अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और यह यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगा।

उन्होंने आगे बताया कि वडोदरा एक प्रमुख कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एवं बिज़नेस हब होने के साथ-साथ एकतानगर एवं धार्मिक स्थलों के कारण यात्रियों का प्रमुख केंद्र है। आने वाले समय में स्टेशन पर 18 महीनों में 4 नए पैदल ऊपरी पुल, दिव्यांगजन सुविधाओं में सुधार तथा हाई-स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि यह डिजिटल लाउंज आधुनिक यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जिसमें हाई-स्पीड वाई-फाई, कार्य-स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट, आरामदायक बैठने की व्यवस्था तथा कॉन्फ्रेंस सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों को प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोकॉपी, चाय-नाश्ता एवं पेय पदार्थों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

यात्रियों के लिए लचीली उपयोग योजनाएं, जैसे अल्पावधि बैठने की सुविधा, प्रति घंटे कार्य-स्थल उपयोग, विस्तारित लाउंज पैकेज, मीटिंग रूम बुकिंग तथा पे-पर-यूज़ सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, अधिक आराम के लिए लाउंजर/रिक्लाइनर सीटिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है।

यह डिजिटल लाउंज 24x7 संचालित होगा और इसमें रियल-टाइम ट्रेन सूचना प्रदर्शन, सीसीटीवी निगरानी, नियंत्रित प्रवेश, उन्नत शौचालय एवं कैशलेस भुगतान प्रणाली उपलब्ध होगी। स्वच्छता, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह पहल वडोदरा रेलवे स्टेशन को आरामदायक, आधुनिक और उत्पादक यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पश्चिम रेलवे की यात्री-केंद्रित सेवाओं को नई ऊंचाई देगा।